मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल मंडफिया के भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में 29 मई, चतुर्दशी को भंडार खोला गया। एक जून को भंडार की राशि की गणना के दूसरे चरण में एक करोड़ 27 लाख 84 हजार रुपए की राशि नकद मिली तथा 29 मई को हुई पहले चरण की गणना में 4.90 करोड़ रुपए मिले थे। अब तक 6 करोड़ रु. से ज्यादा की राशि मिल चुकी है और 100 ग्राम वजन के 20 गोल्ड बिस्किट भी मिले हैं। बताया जाता है कि, मंदिर कार्यालय से प्राप्त सोना-चांदी का वजन करवाना तथा छोटे -बड़े नोटों व सिक्कों की गिनती करना अभी बाकी है। गणना मंदिर बोर्ड अध्यक्ष भैंरुलाल गुर्जर की देखरेख में चल रही है। बताया जाता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ मंडफिया का भंडार हर माह चतुर्दशी या अमावस्या पर खुलता है और चढ़ावे में आए नोटों व सोने-चांदी की गणना होती है। यह प्रक्रिया 4-5 दिनों तक चलती है।

'मुख्यमंत्री जी गर्भ के बच्चे की उम्मीद में गोद वाले को छोड़ना बंद कीजिए'

मोहन प्रकाश बोले, कांग्रेस के मूल वोट बैंक को छोड़कर ऐसे लोगों को सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, जो वोट बैंक नहीं हैं

- खाचरियावास बोले, जनता का काम अटकाने वाले अफसरों का इलाज जरूरी।

जयपुर, 1 जून (का.प्र.)। उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में आयोजित दो दिवसीय एक्शन टेकन कैंप में नेताओं के निशाने पर सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली नेताओं के निशाने पर रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप गर्भ वाले बच्चे की उम्मीद में गोद वाले को छोड़ना बंद कीजिए।

कांग्रेस का मूल "वोट बैंक" है, हम उसकी चिंता नहीं करते, उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देते। इनकी जगह ऐसे लोगों को सत्ता में भागीदारी देते हैं जो वोट बैंक नहीं है। यह गोद वाले बच्चे को छोड़कर गर्भ वाले की चिंता करने की तरह है। इससे पार्टी का हित नहीं होगा।

मोहन प्रकाश ने आगे कहा कि कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है तो वहां चंद नेता रहते हैं। इन प्रदर्शनों से जनता नहीं जुड़ पाती। महंगाई सहित कई मुद्दे पर जनता में मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री गांधीवादी हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस के कुछ नेता माहौल खराब करते हैं। उनका इलाज करने के लिए लोकल नेताओं को ताकत देना जरूरी है।

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनता के काम अटकाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का सुझाव देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने में कई अफसर रोड़ा अटका रहे हैं। उनका इलाज करना जरूरी है। बाहर आकर खाचरियावास बोले कि मैंने आज बैठक में बोला है कि कई अफसर महान हैं। जो प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बांटने में बाधा बन रहे हैं। बेवजह फाइलें घुमा कर डिले कर रहे हैं। अब जनता की पट्टों से जुड़ी फाइलें घुमाने वाले अफसरों को घुमाने का वक्त आ गया है। अफसरशाही का रवैया ठीक नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस नेता मनोबल उंचा रखें और ग्राउंड तक सरकार के काम को पहुंचाएं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊपर रखने के लिए सबको साथ लेकर जनता में एकजुटता से मैसेजे देना होगा।

इससे पहले शिविर की शुरुआत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चिंतन शिविर के फैसलों को धरातल पर लागू करने पर नेताओं के सुझावों को सौ फीसदी लागू करना संभव नहीं होगा। फाइनल फैसला एआईसीसी के स्तर पर होगा। यह कतई नहीं माना जाए कि जो कह दिया वह लागू होगा।

'यह मनी लॉण्डरिंग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी परिवार की 86 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कांग्रेस ने कहा कि यह प्रकरण ऋण को ईक्विटी में बदलने, ताकि कर्मचायिों को वेतन जैसी बकाया राशियों का भुगतान किया जा सके से संबंधित था। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महँगाई जैसे "असली मुद्दों" से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। सिंघवी ने कहा कि ई.डी.ने उक्त केस 2015 में बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने संबंधित अधिकारियों को हटा दिया, नये अधिकारी लगाये तथा उसी केस को फिर से खोल दिया।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए.) की क्रिमिनल धाराओं के अन्तर्गत, उनके बयान रिकॉर्ड करना चाहती है।

नैशनल हैरल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) तथा मालिक यंग इंडियन प्रा. लिमिटेड है। यह केस धोखाधड़ी, साजिश तथा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) के अधिग्रहण में यंग इंडियन प्रा.लि. द्वारा किये गये क्रिमिनल न्यास-भंग/विश्वास भंग (बीच ऑफ ट्रस्ट) से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.ए.) नैशनल हैरल्ड का संचालन करती थी।

इस केन्द्रीय जाँच एजेंसी ने, जांच पड़ताल के एक हिस्से के रुप में, हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पवन बंसल से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं तथा गांधी परिवार से पूछताछ किया जाना जांच पड़ताल का हिस्सा है ताकि शेयर होल्डिंग के पैटर्न, वित्तीय लेनदेन तथा यंग इंडियन एवं ए.जे.एल के प्रमोटरों की भूमिका को समझा जा सके।

एजेंसी ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में दायर की गयी एक प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत के आधार पर, पीएमएलए की क्रिमिनल धाराओं के तहत एक नया केस दर्ज किया है। इस नये केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने छल-कपट एवं धोखाधड़ी की तथा यंग इंडिया के साथ मिलकर पैसे का दुरुपयोग किया तथा 50 लाख रुपये की रिश्वत देकर उस 90.25 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के अधिकार प्राप्त कर लिये जो ऐसे सिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का कर्ज था।

इस प्रकरण में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तथा यह मुकदमा दिल्ली की अदालत में अब भी लंबित है। सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी इस केस में जमानत ले चुके हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने इस मामले में पीएमएलए जांच शुरु कर दी है, जो "गैर कानूनी" है।

सिंघवी ने आगे कहा कि ए.जे.एल.का फर्जी मुद्दा भाजपा के प्रचार तंत्र की एक कोशिश मात्र है ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, गिरती हुई जीडीपी, सामाजिक बेचैंगी एवं अशांति, देश का सामाजिक विभाजन के विभिन्न प्रकार के जबरदस्त मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया, मोड़ा तथा भटकाया जा सकेंऋ। मैं यह सब एक मिनट में आपके सामने प्रदर्शित करूंगा।

'हमने बी.जे.पी. पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई'

मुख्यमंत्री गहलोत ने एक दिन पहले जो तंज किया था उसका अपने तरीके से जबाब दिया पायलट ने

- क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती, एक बार 50 और 1 बार 21 कैसे रह गए।
- कहा गया जो माहौल बना है मोदी जी के आने के बाद, लेकिन इससे पहले भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पा रहे थे।

जयपुर, 1 जून (का.प्र.)। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे 19 साथी गुमराह होकर चले गए थे, वह भी साथ हैं। इस बात के जरिए उन्होंने सचिन पायलट पर सियासी निशाना साधा था, लेकिन सचिन पायलट ने इस बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली को ही फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल ईडी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस देकर बुलाने के मामले को जोड़ते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान में जब भाजपा सत्तारुढ़ थई और कांग्रेस विपक्ष में तब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे लेकिन अब कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजूद उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

पायलट ने भाजपा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार और उसमें आरोपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर खुलकर नाराजगी जताते हुए जयपुर में कांग्रेस एक्शन टेकन कैंप में कहा की भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सत्तारुढ़ नेताओं पर हमने आरोप लगाए थे। हमारे भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता ने स्वीकार भी किया था, और उन्हें सही मानकर हमें सत्ता सौंपी लेकिन हमने अब तक क्या कार्रवाई की ? ऐसे नहीं होता है। वह हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं। हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत की पहचान करना जानते हैं।

सचिन पायलट ने कहा कि हमारे नेताओं को टारगेट किया गया। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या ऐसा कभी किसी ने पहले किया है। सोनिया गांधी और उनके परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई, मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे नेताओं को यातनाएं दी जा रही हैं, बेल लेने पर मजबूर किया जा रहा है। पिछले आठ साल में केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के साथ जो कुछ किया वह सबको दिख रहा है।

इससे पहले सुबह भी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होने को लेकर कहा कि हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे एक बार सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार 21 विधायक रह गए थे। ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है। हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में रिपीट हो चुकी, असम में रिपीट हो चुकी, आंध्रा में रिपीट हो चुकी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है। राजस्थान में किन कारणों से सरकार रिपीट नहीं हो पाती है तो उन कारणों पर चर्चा भी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद सभी जगह हार के बहाने बनाए जाने की बात को लेकर भी पायलट ने कहा कि इससे पहले भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पा रहे थे। इन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। कार्यशाला में संकल्प भी लेंगे कि कैसे एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रपीट हो। उन्होंने कहा कि मैंने जो सुझाव दिए, मैं एआईसीसी, सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं कि उन विचारों को उन्होंने स्वीकार किया। हमारे सुझावों पर समिति बनाई। उसने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही समय पर सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे तभी रिपीट करवाएंगे। सरकार रिपीट करने के लिए सब की मंशा है कि सरकार रिपीट हो। मुझे भरोसा है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे। सही कदम उठाएंगे और पहले जो भी कमी रह रही हो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी सरकार रिपीट हो जाएगी।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में आयोजित कांग्रेस के "एक्शन टेकन कैंप" को संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि बीजपी राज में जब कांग्रेस विपक्ष में थी और सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उस दौरान खान आवंटन में हुए घोटाले सहित अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किए थे।

कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। लेकिन इसके बाद जब 2018 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन गई तो खान घोटाले की गडबड़ियों पर कांग्रेस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब पार्टी मंच पर सचिन पायलट ने खान घोटाले सहित अन्य मामलों में भाजपा नेताओं पर कार्यवाही नहीं होने को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

वैसे सचिन पायलट में सियासी रूप से अशोक गहलोत पर ना सिर्फ हमला किया है, बल्कि उन बातों का भी जवाब दिया है, जिनके जरिए मुख्यमंत्री कई मौकों पर सचिन पायलट पर बिना नाम लिए हमला करते हैं। इतना ही नहीं जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस देकर बुलाया है ऐसे मौके पर सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं और भाजपा सरकार के घोटालों पर कार्यवाही नहीं होने का मुद्दा उठाकर एक तरह से कार्यकर्ताओं को भी बहस के लिए नया विशेष दे दिया है।

'बसपा के दल-बदलू विधायकों को वोट देने से रोका जाए'

जयपुर, 1 जून। बसपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को पत्र लिखकर अपील की है कि, बसपा से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में आये विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से रोका जाये।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि, 2018 में बसपा के सिम्बल पर 6 विधायक चुनाव जीतकर आये थे और उन्होंने असंवैधानिक तरीके से बसपा का कांग्रेस में विलय कर दिया था। इन विधायकों का यह कृत्य संविधान विरुद्ध है और दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन है।

- बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधानसभा स्पीकर डॉ.सी.पी. जोशी को पत्र लिखकर अपील की है कि बसपा से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में आए विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, इन 6 विधायकों राजेन्द्र गुढ़ा, लाखन सिंह,दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगेन्द्र सिंह अवाना व वाजिब अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलबदल विरोधी कानून की अवमानना का मामला चल रहा है, शीघ्र ही उस पर फैसला होने वाला है।

उन्होंने कहा कि, इन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये।

दिल्ली सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। अदालत ने कहा दिल्ली सरकार पिछले तीन वर्षों से "दिल्ली हैल्थ बिल, 2019" लागू करना चाहती है, परन्तु आज तक यह कानून तैयार नहीं हो पाया है। अदालत का दिल्ली सरकार को सुझाव है कि जब तक "दिल्ली हैल्थ बिल" 2019" को पूरी तरह तैयार कर लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पारित "क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट" को ही दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर दिया जाता।

जैसा कि विदित है "क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट" केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून है, जो कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में अक्षरश: लागू किया है। इस कानून में पैथ लैबों की तीन श्रेणियों में बांटा गया है, "एडवांस, मीडियम और बेसिक"। इस कानून में तीनों श्रेणियों की लैबों में कौन-कौन से टैस्ट किये जा सकते हैं इसकी जानकारी भी दी गई है और यह भी बताया गया है कि यह टैस्ट किस लेवल तक प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में किये जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी "एडवांस" और "मीडियम" लैबों में एम.डी. पैथोलोजिस्ट ही लैब के टैस्ट रिपोर्ट हस्ताक्षरित कर सकते हैं।

न्यायाधीश मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बिजॉन कुमार मिश्रा तथा अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं और मामले की अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की है।

गजेन्द्र सिंह व तोमर चुनाव प्रभारी

जोधपुर 1 जून (का.सं)। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा जोधपुर सम्भाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने एक आदेश जारी कर राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए है।

जोधपुर सांसद एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय कृषि मंत्री एन एस तोमर को राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को कर्नाटक और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।

पैसिफिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिलचस्पी का कारण वहां की समुद्री भू-सम्पदा है।

प्रशांत महासागर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजी बेड़ों का प्रभुत्व है और चीन यहां पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना चाहता है। चीन ने हाल ही में सोलोमन आईलैण्ड्स के साथ एक सुरक्षा करार किया है जो उसे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह वहां पर चीन के निवेशों की सुरक्षा के लिए किसी उपद्रव को शांत करने को लेकर अपनी सेना भेज सकता है और वाणिज्यिक व सैन्य उपयोग के लिए कोई बन्दरगाह बना सकता है।

फिजी और सोलोमन आईलैण्ड्स में अमेरिका अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह इस मामले में काफी पीछे है।

जमीनी हकीकत:प्रशांत क्षेत्र के कई द्विपीय राष्ट्र अपने यहां महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना नहीं चाहते, लेकिन वे जो चाहते हैं और जो चीन फिलहाल वह सबसे अच्छी तरह से उपलब्ध करवा रहा है, वह है उनका लगातार सहयोग और क्षमता निर्माण।

उद्धरण योग्य:-न्यूजीलैंड की मैसे युनिवर्सिटी में सुरक्षा अध्ययनों की सीनियर व्याख्याता अन्ना पावेल का कहना है कि "प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की असरदार उपस्थिति नहीं है।" उनके अनुसार "मुझे हमेशा इसे लेकर आश्चर्य होता है कि "वांशिगठन सरकार सोचती है कि प्रशांत क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है जबकि वास्तव में बिल्कुल नहीं है।

अमित शाह का सौरव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक नये अध्याय की शुरुआत उस समय नहीं हो सकी थी, लेकिन ऐसे आसार एवं अनुमान है कि वह शुरुआत इस समय हो सकती है। चुनावों से पहले, चूंकि गांगुली के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं जोरों पर थी, इसलिए अन्य लोगों के साथ ही, उनकी पत्नी का भी इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने कहा था कि गांगुली को निश्चित रुप से बहुत सारी अन्य चीजें एवं क्षेत्र पसंद हैं।

लेकिन गांगुली ने इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वे जो कुछ भी करेंगे, उस काम के शीर्ष बिन्दु पर ही होंगे, जैसे वे क्रिकेट में थे। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि अगर वे भाजपा का हिस्सा बनते हैं, तो गांगुली के कथन एवं उनकी प्रकृति के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के सर्वोच्च दावे पर होने चाहिए। गांगुली के प्रति भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस दोनों ही अपना स्नेह दर्शाकर, उन्हें अपनी तरफ लेना चाह रही थी।

यह जानकारी मिलने के बाद की गांगुली को सुनने में कोई समस्या है तथा वे अस्पताल में भर्ती हैं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस नर्सिंग होम में उन्हें देखने गई थीं।

तृणमूल कांग्रेस भी उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती आ रही है। लेकिन यह सुस्पष्ट है कि तृणमूल में गांगुली की भूमिका गौण रहेगी। पार्टी का स्वामित्व एवं संचालन ममता बनर्जी के पास तथा इन दिनों उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास है। और इन दोनों ही बिन्दुओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

इस प्रकार, अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सौरव गांगुली किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वह भाजपा ही होगी। यह सोचने का कोई कारण नजर नहीं आता कि टी.एम.सी. में वे किसी सहायक या अधीनस्थ की भूमिका में रहना पसंद करेंगे,जबकि भाजपा उन्हें राज्य के सर्वोच्च राजनैतिक पद की पेशकश करने को तैयार है। लेकिन इस बात को कम महत्व देना ही उचित है। गांगुली ने अभी तक किसी भी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। लेकिन बी.सी.सी.आई. ने अपनी ओर से ही इस बात से इंकार किया है कि बी. सी.सी.आई. छोड़ने की गांगुली की कोई योजना है।

बी.सी.सी.आई. ने एक बयान में कहा है कि बी.सी. सी.आई.के समक्ष इस समय कई नये कार्यों एवं पहलों की सूची है, जिनमें गांगुली की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका रहेगी।

- अब यह अधूरा काम पूरा किया जायेगा।
- तृणमूल कांग्रेस व भाजपा, दोनों सौरव को अपनी-अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, पर गांगुली का झुकाव भाजपा की ओर है। क्योंकि, भाजपा में गांगुली शीर्षस्थ पद (मु.मंत्री के पद) तक पहुंचाने की आशा रख सकते हैं, पर, तृणमूल में यह पद ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक के लिये आरक्षित है।

रघु शर्मा की यह बात सही साबित होगी : राजेन्द्र राठौड़

- राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, रघु शर्मा ने कहा था कि, 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस 10-15 सीटों पर सिमट जायेगी।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 8 साल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया की प्रेस वार्ता।

जयपुर, 1 जून (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 8 साल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी महत्वपूर्ण बिन्दु रखे। डॉ. पूनिया के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी और ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर इत्यादि उपस्थित रहे।

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि देश के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2014 में नरेन्द्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सुंदर सनातन देश की व्यवस्था में ऐसे अनेको अवसर आये जब देश को चुनौतियों का मुकाबला करना करना पड़ा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक संघर्ष व बलिदान की कहानियां सबको ज्ञात हैं। उन्होंने कहा कि हम आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश में आजादी के आंदोलन के दौरान व उसके बाद की व्यवस्था में एक मिथक था, धारणा थी, कि देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। ऐसा प्रचारित भी किया गया। इसके बाद यह कहा गया कि देश पर शासन करने का हक कांग्रेस को है, उसके बाद यह स्थापित किया गया कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई शासन कर सकता है तो वह नेहरू-गांधी खानदान कर सकता है, 75 वर्षों की आजादी में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और एक खानदान विशेष ने देश पर शासन किया। कहने को कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक था, लेकिन उनके हिस्से में आपातकाल भी था, यातनायें थी, प्रतिबंध भी थे। इसी तरह बार-बार लोकतंत्र व संविधान की बात करने वाले कांग्रेस के लोगों के माथे पर वो कलंक भी था, जिसमें 100 भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता-बहनों की बिडंबना देखिये जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुये, यह बदलाव की पहली शुरुआत थी।

सामान्य व्यक्ति के बैंक के खाते नहीं थे, आज आपको आसान लगता होगा, बैंक खातों से क्या परिवर्तन होता होगा, यह भी आपने देखा है। 45 करोड़ जनधन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी है और भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है।

उन्होंने कहा कि आज भारत की शत प्रतिशत आबादी के पास गैस कनेक्शन हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता-बहनों को धुंए से आजादी दिलाई है। यह बुनियादी बदलाव की बड़ी शुरुआत थी।

आज देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, 3 करोड़ लोगों ने इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ लिया है।

इस अवसर पर राजेन्द्र राठौड़ ने कहा की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे व गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा की यह बात सही साबित होगी कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस 10-15 सीटों पर सिमट जायेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब चौथी बार बाडाबंदी करेंगे, मुख्यमंत्री हॉर्स ट्रेडिंग करते-करते हाथी को ही निकल गये, इनके विधायक इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने के लिये मुख्यमंत्री बाड़ेबंदी का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कुशासन की हकीकत-बेरोजगारी, संस्थागत भ्रष्टाचार, पैट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वैट, पटरी से उतर चुकी कानून व्यवस्था, पेपर लीक इत्यादि लंबी फेहरिस्त है विफलताओं की।

'नैशनल ग्रीन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थिति पैदा होगी। अधिकारियों के सामने यह मुश्किल खड़ी हो जायेगी कि कौन से आदेश माने जायें। इस प्रकार की स्थिति में, संवैधानिक अदालतें सरकार ट्रिब्यूनलों पर प्रभावी मानी जायेगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908